जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 29 संख्याः 326 प्रभात उदयपुर, बुधवार 28 सितम्बर, 2022 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

गंभीर रुप से संकटग्रस्त गुआम किंगफिशर जल्दी ही गुआम के समीपवर्ती जंगलों में वापस आ जाएंगे। नेचर कंज़र्वैन्सी और फिश एण्ड वाइल्डलाइफ सर्विस के बीच सहभागिता से एक वैज्ञानिक मिशन की शुरुआत हुई है। योजना यह है कि, इन पक्षियों की अगले वर्ष वापसी की जाए, गुआम में नहीं, बल्कि पालमीरा एटॉल के जंगलों में, क्योंकि उनके सरवाइवल की यही एकमात्र उम्मीद है। गुआम किंगफिशर के लिए सब कुछ अच्छा था, पर तब तक ही, जब तक कि गुआम के जंगलों में संयोगवंश ब्राउन ट्री स्नेक का आगमन नहीं हुआ था। उसकी वजह से ना केवल यह प्रजाति, बल्कि गुआम के जंगल में रह रहे सभी पक्षी लुप्त हो गए। उसके बाद गुआम किंगफिशर, जिसे स्थानीय भाषा में सिहेक कहा जाता है, की रिकवरी का कार्यक्रम चलाया गया। जब तक गुआम के जंगलों में मंडराता, ट्री स्नेक्स का खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए उनके लिए ऐसी जगह ढूंढी जा रही है जहां वो आराम से रह सकें, हालांकि अंतिम लक्ष्य गुआम में इनकी वापसी ही है। पालमीरा एटॉल गुआम के पास ही है। एटॉल में इन पक्षियों को सफलतापूर्वक छोड़े जाने के बाद गुआम में इसी प्रकार के अन्य रिकवरी कार्यक्रमों की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है अन्तः प्रजनन को रोकना, जो इन पक्षियों के जीवन काल पर प्रभाव डालता है। ज़ुओलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंदन के डॉ. जॉन एवन, जो सिहेक रिकवरी टीम के प्रमुख भी हैं, ने कहा कि हमारे पास इस पक्षी को जंगल में पुनः बसाने का अवसर है पर यह हमें सावधानी से करना होगा। टीम के समक्ष सबसे पहले 2020 में चुनौती आई थी जगह ढूंढने की। पहले इनके लिए कोको आइलैंड्स को चुना गया पर वहां भी ब्राउन ट्री स्नेक की आबादी मिली। इसके बाद पालमीरा एटॉल को चुना गया। पालमीरा में एक फायदा यह भी है कि यहां साइन्टिफिक रिसर्च स्टेशन भी है।

अजय माकन-खड़गे ने जयपुर की बगावत पर नौ पेज की रिपोर्ट दी सोनिया गांधी को

गहलोत के खास कारिन्दे, शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेन्द्र राठौड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। राजस्थान समाप्त होने में अभी समय लगेगा। अजय माकन कमेटी ने साफ तौर पर कह दिया है कि विद्रोह अशोक गहलोत के इशारे पर हुआ था तथा सब कुछ उनके निर्देश एवं देख-रेख में चला था।

सूत्रों का कहना है कि क्लीन चिट का प्रश्न ही नहीं है, जैसा कि अधिकांश राष्ट्रीय मीडिया तथा टी.वी. चैनल निष्कर्षतः कह रहे हैं।

उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ ने आज अशोक गहलोत से दो बार बात की तथा उनसे इस्तीफा देने के लिये कहा, लेकिन समझा जाता है कि उन्होंने यह बात मानने से इंकार कर दिया।

तद्नुसार, वे बड़े नेता, जो 90 से अधिक विधायकों की परेड करा रहे थे, मुश्किल स्थिति में हैं तथा इस पेचीदा स्थिति से नहीं निकल पा रहे हैं।

बताया जाता है कि सोनिया गांधी उस रात की घटनाओं से बहुत अशांत एवं व्यथित हैं क्योंकि वे गहलोत पर आँख बंद कर के विश्वास करती थीं तथा उन्होंने पार्टी की बागडोर उन्हें सौंपने का मानस बना लिया था।

- **अब गौरतलब बात यह है कि, क्या गहलोत अपने खास कारिन्दों के साथ खड़े रहेंगे या उनकी बलि चढ़ाकर आगे बढ़ेंगे।**
- **कारिन्दों के खिलाफ कार्यवाही, सीधे मु.मंत्री के खिलाफ कार्यवाही मानी जाती है और वैसे भी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि, उस रविवार की रात का सारा ड्रामा गहलोत के निर्देश पर तथा उनकी निगरानी में खेला गया था।**
- **पर, दूसरी ओर उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार मंगलवार को दिन में दो बार कमलनाथ ने गहलोत से बात की तथा इस्तीफा देने की सलाह दी, पर गहलोत राय स्वीकार करने की मनःस्थिति में नहीं थे।**
- **वरिष्ठ नेता व ए.आई.सी.सी. की अनुशासन समिति के अध्यक्ष ए.के. एंटनी को दिल्ली बुलाया गया है और अनुशासन कार्यवाही तय करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है।**

सूत्रों ने कहा कि यह सोनिया के लिये पीठ में छुरा भौंकने जैसा कृत्य है।

अजय माकन तथा खड़गे ने अपनी 9 पृष्ठों की रिपोर्ट सोनिया गांधी के पास भेज दी है जिसमें गहलोत को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है जिन्होंने इसे पूरे घटनाक्रम को उकसाया तथा उन्हें दोषमुक्त नहीं माना जा सकता।

माकन जब सोनिया गांधी से मिले तो उन्होंने सोनिया से यह बात कह दी तथा इसे अपनी रिपोर्ट में भी अंकित कर दिया।

गहलोत के दाँये तथा बाँये हाथ माने जा रहे लोग जो विधायकों को बहकाने तथा प्रलोभन देने में सक्रिय रहे, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा कर दी गई है। ये हैं- शान्ति धारीवाल, महेश जोशी तथा धर्मेन्द्र राठौड़, जो गहलोत के मनी बैग हैं।

देखना यह है कि गहलोत इस सब पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, जो उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे या उनकी कुर्बानी देंगे और आगे बढ़ जायेंगे।

वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, जो ए.आई.सी.सी. की अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, आज रात दिल्ली पहुँच रहे हैं तथा उसके बाद ही, गहलोत के इन समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही शुरु होगी।

इस बीच, सचिन पायलट आज शाम दिल्ली पहुँचे क्योंकि अब कार्यवाही का स्थल दिल्ली हो गया है। समझा जाता है कि पी.सी.सी. अध्यक्ष डोटासरा जो इस पूरे घटनाक्रम में खामोश बने रहे थे तथा अशोक गहलोत के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, भी हटाये जाने वालों की कतार में हैं।

पहले भी कई बार कई मु.मंत्रियों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला है

गत पचहत्तर साल में से 42 साल गांधी परिवार के पास रहा है अध्यक्ष पद

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। वस्तुस्थिति यह है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गये हैं लेकिन भारत की इस शानदार अतीत वाली पार्टी में ऐसे कई पूर्वोदाहरण है, जब कार्यरत मुख्यमंत्रियों ने राज्य की जिम्मेदारी को छोड़कर, संगठन के सर्वोच्च पद का दायित्व ग्रहण किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष पद आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में कुल मिलाकर 42 वर्ष गांधी परिवार के पास रहा है तथा गैर-गांधी नेताओं के पास यह पद 33 वर्ष रहा है। सीताराम केसरी ऐसे अंतिम गैर-गांधी नेता थे, जिन्होंने शरद पवार तथा राजेश पायलट को चुनाव में हराकर 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था।

सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष का पदभार 1998 में ग्रहण किया था तथा

- **निजलिंगप्पा ने कर्नाटक के मु.मंत्री पद से त्यागपत्र देकर 1968-69 में कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली थी।**
- **1954 में प्र.मंत्री प. नेहरू ने सौराष्ट्र के मु.मंत्री ढेबर भाई को सौराष्ट्र से बुलाकर कांग्रेसाध्यक्ष पद संभलवाया था।**
- **इसी प्रकार 1963 में तमिलनाडू के मु.मंत्री का पद छोड़कर के. कामराज ने दिल्ली आकर कांग्रेसाध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली थी।**

वे इस पद पर, 2017 से 2019 तक की अल्पावधि के अलावा लगातार बनी हुई हैं। ज्ञातव्य है कि 2017 से 2019 तक राहुल गांधी इस पद पर रहे थे। 1948 के बाद बने 16 कांग्रेस अध्यक्षों में से पाँच अध्यक्ष गांधी परिवार से रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा लम्बे समय तक पार्टी अध्यक्ष रहने वाली सोनिया गांधी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष रहे गैर-गांधी नेताओं में शामिल प्रमुख नाम हैं- नीलम संजीवा रेड्डी, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ तथा पी.वी. नरसिम्हा राव।

पार्टी अध्यक्ष बनने के लिये मुख्यमंत्री पद छोड़ देने वालों में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा (1968-69) भी शामिल हैं। लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था, जिसका उन्हें अफसोस रहा। जैसा कि निजलिंगप्पा ने अपनी आत्मकथा "माइ लाइफ एंड पॉलिटिक्स" में लिखा है: "कई कारणों से, मुझे उस निर्णय पर आज भी अफसोस होता है। अगर मैं मैसूर का मुख्यमंत्री बना रहता तथा मैंने (अध्यक्ष पद की) दुर्वह जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया होता, तो हर नजरिये से मेरे लिये बेहतर रहता।" बहुत वर्ष पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री यू.एन. ढ़ेबर को 1954 में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। जहाँ तक ढ़ेबर का मामला है, उस समय यह सुविदित था कि सौराष्ट्र का बम्बई में विलय हो जायेगा और 1956 में ऐसा हो भी गया था।

तमिलनाडु के के. कामराज भी 1963 में मुख्यमंत्री पद छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा उन्होंने मुख्यमंत्री पद एम. भक्तवत्सलम को सौंप दिया था। उल्लेखनीय है कि कामराज तमिलनाडु के अंतिम कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे।

'इस्तीफे स्वीकारने ही होंगे'

जयपुर, 27 सितम्बर (का.सं.)। प्रदेश चल रहे सियासी संकट के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि इस समय राजस्थान में प्रशासनिक, वैधानिक और संवैधनिक तीनों प्रकार के संकट पैदा हो गए हैं। संवैधानिक संकट यह है कि विधानसभाध्यक्ष

- **वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि, अगर स्पीकर को इस्तीफा भेजा जाता है तो, नियमानुसार उन्हें इस्तीफे स्वीकारने ही पड़ेंगे।**

(स्पीकर) को विधायकों ने इस्तीफे सौंपे हैं, ऐसे में इन इस्तीफों को स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर वो इस्तीफे स्वीकार नहीं करते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने आलाकमान के खिलाफ रोष प्रकट करने का माध्यम स्पीकर को जरिया बनाया है। स्पीकर के पास अगर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मौखिक व लिखित रिपोर्ट में इतना फर्क क्यों है?

खड़गे ने अपनी रिपोर्ट में कहा बताया कि, गहलोत की ''बगावत'' में कोई भूमिका नहीं थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बुधवार को दिल्ली जाने और वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह समझाने की उम्मीद है कि उनके धुर प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट को उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाओं के खिलाफ उनके समर्थकों द्वारा विद्रोह का झण्डा उठाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

यही नहीं गहलोत पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी भर सकते हैं, बशर्ते पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें यह संकेत मिल जाए कि उनकी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए किसी और व्यक्ति को पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा।

स्थिति मंगलवार को तब बदली जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया को एक लिखित रिपोर्ट देकर मामले की एक बेहतर छवि पेश की। इसमें तर्क दिया गया कि पार्टी विधायकों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट हैं कि गहलोत की विद्रोह में कोई भूमिका नहीं थी। एक अलग परिदृष्य तब उभरा जब सोनिया गांधी ने खड़गे और राजस्थान में ए.आई.सी.सी. के प्रभारी महासचिव अजय माकन, दोनों से रिपोर्ट मांगी थी। माकन और खड़गे को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाने वाली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **गहलोत बुधवार को दिल्ली जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, सोनिया गांधी के सामने।**
- **अंबिका सोनी ने भी खड़गे से बात करके अपना निर्णय सुनाया कि, गहलोत निर्दोष हैं।**
- **अगर गहलोत के निर्दोष होने की कहानी स्वीकार हो जाती है तो वे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिये हाई कमान के उम्मीदवार हो सकते हैं।**
- **पर, ए.आई.सी.सी. का एक इतना ही सशक्त वर्ग गहलोत को उम्मीदवार बनाने के सख्त खिलाफ है। उनका तर्क है, जो मु.मंत्री के रूप में अपने समर्थकों को नहीं संभाल पाया, वो अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी स्थिति का कैसे सामना करेगा।**

इलैक्ट्रिक कार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। चीन का घरेलू इलैक्ट्रिक कार मार्केट वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष देश में खरीदी गई करीब एक चौथाई नई कारें इलैक्ट्रिक या प्लग इन हाईब्रिड होंगी। चीन में इतनी इलैक्ट्रिक कारें बेची जाएंगी जितनी शेष दुनिया में मिलाकर भी नहीं बेची जाएंगी।

- **चीन का घरेलू इलैक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पूरे विश्व की तुलना में चीन में सबसे ज्यादा इलैक्ट्रिक कारें बिकी हैं।**

कुछ अनुमानों के अनुसार प्रतिद्वंदी टैस्ला और जर्मन ऑटोमेकर्स की तुलना में तीन सौ से अधिक चाइनीज़ कम्पनियां 5 हजार डॉलर से कम और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायक दल की समानांतर बैठक के लिए मुख्यमंत्री के नजदीकी धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेन्द्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस

माकन और खड़गे की रिपोर्ट में मु.मंत्री गहलोत की भूमिका पर सवाल, लेकिन लिप्त होने के प्रमाण नहीं, इसलिए नोटिस नहीं दिया गया

जयपुर, 27 सितम्बर (का.प्र.)। आलाकमान की ओर से गत 25 सितंबर को जयपुर में बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के समानांतर बैठक कर मुख्य बैठक का बहिष्कार करने तथा इस मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाले संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कांग्रेस आलाकमान की ओर से प्रभारी महासचिव अजय माकन तथा पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का जवाब 10 दिन में मांगा गया है और संतुष्ट नहीं होने पर आलाकमान इन तीनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकता है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नंबर दो शांति धारीवाल और नंबर 3 मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित उनके लिए लगातार काम करने वाले धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका पर सवाल तो उठाए गए हैं,

- **धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेन्द्र राठौड़ को नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।**
- **आलाकमान द्वारा बुलाई गई बैठक के समानान्तर विधायकों की मीटिंग करने में धारीवाल, जोशी और धर्मेन्द्र राठौड़ की प्रमुख भूमिका मानी गई है, इनमें से राठौड़ ही हैं जो विधायक नहीं हैं फिर भी इस मीटिंग में अति सक्रिय थे, वे आर.टी.डी.सी. के चेयरमैन हैं।**

लेकिन उनका सीधे तौर पर शामिल होने के कोई सबूत नहीं होने के कारण उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल पर विधायकों को एकजुट रखने का जिम्मा है और यदि वही अपने घर पर समानांतर बैठक बुला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरुरत समझी गई।

वहीं मख्य सचेतक महेश जोशी का काम सभी विधायकों को विधायक दल की बैठक के आयोजन की जानकारी देने के साथ ही बैठक में बुलाने का जिम्मा है, लेकिन मुख्य सचेतक ने विधायकों को सूचना देना तो दूर, खुद भी बैठक का बहिष्कार किया और संसदीय कार्य मंत्री के घर हुई समानान्तर बैठक में मौजूद रहे। इस कारण वह भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायरे में आ गए हैं।

मुख्यमंत्री के बेहद खास और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ विधायक नहीं है इसके बावजूद भी संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी निवास पर होने वाली समानांतर विधायक दल की बैठक में वे ना सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि बैठक के बाद विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी जोशी के निवास पर बस में बैठाकर ले जाने के समय विक्ट्री साइन दिखाते हुए भी नज़र आए। ऐसे में प्रभारी महासचिव अजय माकन और पर्यवेक्षक मकार्जुन खड़गे की ओर से माना गया कि विधायकों को यहां लाने और ले जाने की व्यवस्था में धर्मेंद्र राठौड़ की भी प्रमुख भूमिका रही है। ऐसे में उन पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दिल्ली पर नियंत्रण

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। पांच जजों की एक संविधान बैंच ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को लेकर केन्द्र और दिल्ली सरकार की शक्तियों के संबंध

- **राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न सर्विसेज़ पर नियंत्रण को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार के बीच विवाद के मुद्दे पर 5 सदस्यों वाली संविधान बैंच 9 नवम्बर से हर रोज़ सुनवाई करेगी।**

में आगामी 9 नवम्बर से दिन-प्रतिदिन की सुनवाई नियत की है।

जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि "जैसा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)